संख्या-85/2017/613/41-2018-22 (बजट)/2017

प्रेषक,

बच्चू लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2018**

विषय-जनपद गोरखपुर के सर्किट हाउस रोड पर स्थित बोट जेटी के पुनरोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7169/6-1-1(850)/2017, दिनांक 09.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद गोरखपुर के सर्किट हाउस रोड पर स्थित बोट जेटी के पुनरोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित आगणन के सापेक्ष रू0 83,89,000.00 (रूपये तिरासी लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 41,95,000.00 (रूपये इकतालीस लाख पन्चानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-44/2017/1954/41-2017-22 (बजट)/2017 दिनांक 25.09.2017 द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में दिये गये प्रावधानों/मार्गदर्शी बिन्दुओ के अनुसार आगणनों के परीक्षण हेतु पर्यटन विभाग में गठित समिति से अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा तथा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदान की जा रही प्रशासकीय स्वीकृति उक्त समिति की संस्तुति के अधीन होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त परियोजना के आगणन का परीक्षण लोक निर्माण विभाग से कराते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति की बैठक दिनांक 09 मार्च, 2018 को सम्पन्न बैठक में उपर्युक्त परियोजना के आगणन की धनराशि रू0 77.94 लाख आंकलित/अनुमन्य की गयी है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के सर्किट हाउस रोड पर स्थित बोट जेटी के पुनरोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू0 83.89 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त अनुमन्य लागत रू0 77.94 लाख (सत्हत्तर लाख चौरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख (रूपये पैतीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-डेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही उक्त अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व यह भलीभांति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजना हेतु पूर्व में प्रदान की गयी धनराशियों के सापेक्ष कराये गये कार्य स्वीकृत योजना के निर्धारित स्वरूप/योजना के अनुसार कराया गया है तथा उक्त कार्य में निर्धारित मानदण्डों/गुणवत्ता पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियान्ता सिंचाई विभाग से प्राप्त कर उसकी पुष्टि सक्षम स्तर से सुनिश्चित करा ली जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(9) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्य के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जायेगा तथा अधिरोपित जी0एस0टी0 जमा कराये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने का प्रमाण-पत्र पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए शासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था को सेन्टेज का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्तिच कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

संख्या-85/2017/613/41-2018-22 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर/जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।